एल.आई.सी. आई.पी.ओ - एस. बी.आई. से सबक

थॉमस फ्रेंको (सौजन्य: सीइएनएफए 11 अक्टूबर, 2021)

केंद्र सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम के निजीकरण पर तुली हुई है। उन्होंने केंद्रीय बजट 2021 में बयान देकर LIC अधिनियम में चुपके से संशोधन की घोषणा की और इसे एक अलग संशोधन के रूप में लाने के बजाय इसे वित्त अधिनियम 2021 का हिस्सा बना दिया। एल.आई.सी. की अधिकृत पूंजी 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 25000 करोड़ रुपये कर दी गई है। एल.आई.सी. का बाजार पूंजीकरण लगभग 8 से 10 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि 31 मार्च, 2021 तक इसकी संपत्ति 38 लाख करोड़ रुपये और एल.आई.सी. द्वारा निवेश 3676170 करोड़ रुपये है। पिछले साल अकेले एल.आई.सी. ने 1.84 लाख करोड़ रुपये का नया व्यापार प्रीमियम एकत्र किया और मार्च 2021 में जारी नीतियों के मामले में इसकी बाजार हिस्सेदारी 81.04 फीसदी थी।

केंद्र सरकार, एल.आई.सी. के कुछ अधिकारी और मीडिया का एक हिस्सा यह प्रचार कर रहा है कि एल.आई.सी. सार्वजनिक रहेगा, जबकि वे इसकी तुलना भारत के सबसे बड़े बैंक एस.बी.आई. से करते हैं, जो अभी भी सरकार के पास 56.92% शेयरों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। भारत के (10 अक्टूबर 2021 तक) एफ.आई.आई. के पास 10.42%, गैर-बैंक म्यूचुअल फंड की 12.89%, वित्तीय संस्थानों की 11.5% और आम जनता की 6.26% हिस्सेदारी है, इसके अलावा कुछ अन्य लोगों के पास एस.बी.आई. के शेयरों का एक छोटा प्रतिशत है।

जनता और कर्मचारियों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि क्या एस.बी.आई. सही अर्थों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में व्यवहार कर रहा है और वहां क्या परिवर्तन हो रहे हैं, चिंता के कारण क्या हैं और सीखने के लिए सबक क्या हैं। एस.बी.आई. लोगों का बैंक था, लेकिन अब यह कॉरपोरेट का बैंक ज्यादा हो गया है।

1991 के बाद, एस.बी.आई. पर कई उदारवादी नीतियों को लागु किया गया है। कृषि विकास शाखाओं को, जिनमें एस.बी.आई. अग्रणी था, ध्यान कॉर्पोरेट लेखा समूह (Corporate Accounts Group)शाखाओं में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब उनमें से 8 शहरों में 51 शाखा हैं और मार्च 2021 तक उनका

क्रेडिट 818705 करोड़ रुपये है, जबकि एसएमई से संबंधित 278949 करोड़ रुपये और कृषि से संबंधित 213000 करोड़ रुपये हैं। आज, SBI की 22219 शाखाएँ हैं, लेकिन इसके 71968 व्यवसाय प्रतिनिधि हैं जो ग्राहक सेवा बिंदु चलाते हैं। ये सभी नियमित कर्मचारी हो सकते थे और एस.बी.आई. की 72000 छोटी शाखाएँ हो सकती थीं।

अब तक बिना किसी रिटर्न के बावजूद एस.बी.आई. जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड के साथ अनावश्यक रूप से 30% शेयरधारिता के साथ जुडी हुई है। एस.बी.आई. के पूर्व अध्यक्ष अब रिलायंस बोर्ड का हिस्सा हैं। जियो ने 71000 आउटलेट खोलने की घोषणा की है जो एसबीआई के लिए एक प्रतियोगी होगा, और अंत में उनका लक्ष्य एस.बी.आई. को हड़पना हैं। उनकी रणनीति लंबी अवधि के लिए है। जब अखबार और मीडिया आलोचनात्मक लग रहे थे, तो उन्होंने मीडिया घरानों को खरीद लिया और अब उनके पास 72 टीवी चैनल हैं। जिस दिन सरकार अपनी हिस्सेदारी को 50% से कम करने का निर्णय लेती है, उस दिन एस.बी.आई. का अधिग्रहण संभव हो जाएगा। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा संसद में किए गए पहले के वादों के खिलाफ, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए अगले संसद सत्र में राष्ट्रीयकरण अधिनियम में संशोधन की उम्मीद है। इसमें एस.बी.आई. एक्ट में संशोधन कर एस. बी.आई. को भी शामिल किया जा सकता है।

एस.बी.आई. के बोर्ड में 4 शेयरधारक निदेशक हैं। उनमें से कोई भी अल्पसंख्यक शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। 2014 के बाद कोई कर्मचारी निदेशक और अधिकारी निदेशक नहीं है, हालांकि अधिनियम में इसके लिए प्रावधान है। कोर्ट के निर्देश के बाद भी पी.एम.ओ को कोई फर्क नहीं पड़ता। एस.बी.आई. ने एक कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना की पेशकश की, जिसे कई कर्मचारियों द्वारा खरीदा गया था, शायद यह मानते हुए कि वे बैंक के मालिक होने जा रहे हैं, लेकिन शेयर की कीमतें बढ़ नहीं रही हैं। उतार-चढ़ाव आए हैं। एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को शेयरधारक निदेशक के रूप में चुनने का वित्त मंत्रालय का प्रयास, जिसके पास जबरदस्त शक्ति है, बुरी तरह विफल रहा।

एस.बी.आई. ने 2001 में **FICCI** की एक समिति की सिफारिशों के अनुसार एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वोलंटरी रिटायरमेंट स्कीम)प्रदान किया और इसके कारण 2,30,000 में से 29000 कर्मचारियों ने बैंक छोड़ दिया जिससे ग्राहक सेवा खराब हो गई है। एसोसिएशन और यूनियनों के हंगामे के कारण 2017-18 में

कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 2,64,041 हो गई, जो 2021 में घटकर 2,45,652 हो गई है, जिससे मौजूदा कर्मचारियों का कार्यभार बढ़ गया है और उनके कार्य-जीवन संतुलन नष्ट हो गया है। काम के दबाव से आज बैंक का हर अधिकारी रोता है और कई आत्महत्याएं भी हो चुकी हैं।

अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती पूरी तरह से रोक दी गई है। एस.बी.आई. में कर्मचारी के रूप में नियमित ड्राइवर थे। अब इसे आउटसोर्स किया गया है। सफाई आउटसोर्स की जाती है। कंप्यूटरों का रखरखाव आउटसोर्स किया जाता है। एसबीआई आउटसोर्सिंग में अग्रणी बन गया है। अब नकद प्रबंधन भी आउटसोर्स किया जाता है! बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप द्वारा निर्धारित एक करियर डेवलपमेंट सिस्टम (सी.डी.एस.) एस.बी.आई. में लागू किया गया था। संघों द्वारा इसे 'कैरियर डिस्ट्रक्शन सिस्टम' कहा गया, क्योंकि इसने कर्मचारियों में बहुत अधिक विसंगति, उत्पीड़न और असंतोष पैदा किया, लेकिन अब इसे अन्य बैंकों में आजमाया जा रहा है।

एस.बी.आई. फिर से डिजिटल ऋण देने के लिए सूक्ष्म वित्त संस्थानों के साथ मिलकर एक प्रयोग कर रहा है, हालांकि इसके पास सबसे अच्छा डिजिटल प्लेटफॉर्म है और प्रौद्योगिकी नवाचार में अग्रणी था। यह पहले ही 10 से अधिक एन.बी.एफ.सी. - फिनटेक के साथ गठबंधन कर चुका है। पिछले अध्यक्ष के तहत, एस.बी.आई. ने न्यूनतम शेष राशि सहित सेवा शुल्क में वृद्धि की और कई अन्य बैंकों ने भी इसका पालन किया। वर्तमान अध्यक्ष ने न्यूनतम शेष शुल्क हटा दिया है। 'वित्तीय समावेशन मॉड्यूल' नामक एक और प्रयास की कोशिश की गई लेकिन बाद में उलट दिया गया क्योंकि शुरू में इस्तेमाल होने वाली अनुशंसित मॉड्यूलर संरचना, आईआईएम अहमदाबाद द्वारा मैकिन्से की रिपोर्ट के अनुसार बेहतर अनुकूल थी। साथ ही, सरकार एस.बी.आई. के फैसलों को प्रभावित करती रहती है। वर्तमान अध्यक्ष खुदरा ऋण पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन कॉर्पोरेट ऋण के लिए दबाव जारी है। सरकारी योजनाओं के तहत लक्ष्य पूरा करने के बावजूद सरकारी कारोबार निजी बैंकों की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एस.बी.आई. को यस बैंक में निवेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो अभी भी संघर्ष कर रहा है। अध्यक्ष द्वारा इसके खिलाफ बोलने के बावजूद सहयोगी बैंकों का विलय मजबूर किया गया था।

आई.पी.ओ. खत्म होने के बाद एल.आई.सी. में भी इसी तरह के मुद्दे सामने आएंगे। जनता के साथ रहने का वर्तमान वादा केवल दिखावा है। क्या सिर्फ

90000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए सरकार को आई.पी.ओ. लाना चाहिए जो निजीकरण की दिशा में पहला कदम है? सरकार के बजट में मदद के लिए एल.आई.सी. हर साल निवेश के तौर पर इससे ज्यादा देती है! इसकी बैलेंस शीट पर सरसरी निगाह डालने से पता चलता है। पूरे देश में इसके लगभग 4000 कार्यालय हैं; लगभग 14 लाख की एक एजेंसी बल और 1,09,000 कर्मचारी हैं। इसके पास 3775690 करोड़ रुपये की संपत्ति है। इसका इक्विटी निवेश 663637 करोड़ रुपये और बुनियादी ढांचे में 427870 करोड़ रुपये है। इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो दुनिया में सबसे अच्छा बना हुआ है।

एलआईसी ने बिजली, आवास, पानी की आपूर्ति और सीवेज, सड़कों, पुलों, सड़क परिवहन, रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचे में निवेश किया है। यह देश का विकास कर रहा है। हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 23% बीमा कोष से है। संघ/राज्य सरकार की परियोजनाओं में इसका निवेश 2401456.50 करोड़ रुपये है। केंद्र सरकार के दबाव में एलआईसी ने इसे बचाने के लिए आईडीबीआई बैंक में निवेश किया और 12887 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। एलआईसी का बीमा रिजर्व 1278558.45 करोड़ रुपये है, नकद और बैंक बैलेंस 2841100.06 करोड़ रुपये है, इसके पॉलिसीधारकों को भुगतान किया गया बोनस 5119539.53 करोड़ रुपये है। इसका दीर्घकालिक निवेश 3089499.50 करोड़ रुपये है। इसका पिछले साल का कर पश्चात लाभ 2703.61 करोड़ रुपये है। यह देखना दिलचस्प है कि सरकार ने शुरुआत में एलआईसी में केवल 5 करोड़ रुपये का निवेश किया था, बाकी पूंजी लाभ से जमा की गई है। एलआईसी सरकार को केवल 5% लाभांश का भुगतान करती है, जबकि इसका 95% बोनस के रूप में पॉलिसीधारकों के बीच वितरित किया जाता है। क्या निजी शेयरधारक इसकी अनुमति देंगे? भारत में 24 निजी बीमा कंपनियां हैं, लेकिन एलआईसी का प्रदर्शन उत्कृष्ट बना हुआ है। आइए हम इसे नष्ट न होने दें। एसबीआई से अच्छे सबक सीखें, बुरे नहीं। हमें नव-उदारवादी नीतियों की जरूरत नहीं है जो केवल कुछ ही लोगों की मदद करती हैं। हमें जनहितैषी नीतियों की जरूरत है जिससे बहुसंख्यकों को लाभ हो। कृपया किसी को बलि का बकरा न बनाएं!

(थॉमस फ्रेंको अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ के पूर्व महासचिव हैं)